

20/11/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी अधिवक्ता उपरिथत। विप्रार्थीगण एकपक्षीय। प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थिनी की ओर से विवादित भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बावत अनुतोष चाहा गया है, जिसमें प्रार्थिनी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थिनी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थी आए दिन दंखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उतारू है, यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थिनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतं प्रार्थिनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थिनी राहत प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि की प्रार्थिनी खातेदार नहीं है, जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारान होने के कारण स्थगन आदेश से पांबद नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थिनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,